

कॉन्स्टीट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान का लोकार्पण-विधानसभा 90 करोड़ रुपए की लागत से बना अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित क्लब, चिंतन-मनन से प्रशस्त होगी प्रदेश की तरक्की की राह विचारों के आदान-प्रदान का महत्वपूर्ण केन्द्र बनेगा कॉन्स्टीट्यूशन क्लब -मुख्यमंत्री

चमकता राजस्थान, जयपुर। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान में केवल घोषणाएँ नहीं हुई हैं, बल्कि उन्हें प्रभावी रूप से लागू भी किया गया है। राज्य में गुड गवर्नेंस का शानदार माहौल बना है। यह पहली बार है, जब राज्य सरकार की योजनाओं की पूरे देश में चर्चा हो रही है। राजस्थान मॉडल स्टेट के रूप में उभरा है। इसी क्रम में हमने मिशन-2030 के तहत विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य प्रदेश की तरक्की और खुशहाली के लिए आम लोगों के सुझाव लेना है। अब तक 2 करोड़ से अधिक सुझाव ऑनलाइन व ऑफलाइन माध्यम से प्राप्त हो चुके हैं, जो इसे लेकर प्रदेशवासियों के जन्मे को जाहिर करता है। गहलोत शुक्रवार शाम विधानसभा के पास स्थित विधायक नगर (पूर्व) की भूमि पर निर्मित कॉन्स्टीट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान के लोकार्पण समारोह को सम्बोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने मंत्रोच्चार के बीच कॉन्स्टीट्यूशन क्लब का उद्घाटन किया। उन्होंने एचसीएम रीपा में बनने वाले ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट का शिलान्यास किया तथा विधान सभा में हुई विभिन्न गतिविधियों पर आधारित प्रदर्शनों का अवलोकन भी किया।

प्रशस्त हुई प्रदेश की तरक्की की राह

मुख्यमंत्री ने कहा कि चिंतन-मनन से हमेशा लाभ मिलता है, इससे नए विचार सामने आते हैं तथा देश-प्रदेश की तरक्की का मार्ग प्रशस्त होता है। दिल्ली के कॉन्स्टीट्यूशन क्लब की तर्ज पर निर्मित यह कॉन्स्टीट्यूशन क्लब इस दिशा में एक



महत्वपूर्ण मंच साबित होगा। उन्होंने कहा कि राजस्थान में एक के बाद एक कई महत्वपूर्ण संस्थान स्थापित हो रहे हैं, जिनमें कॉन्स्टीट्यूशन क्लब, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, गांधी म्यूजियम, फिनटेक युनिवर्सिटी आदि शामिल हैं। उन्होंने कहा कि देश में लोकतंत्र की एक स्वस्थ परंपरा रही है। पक्ष-विपक्ष के सदस्यों के बीच संबंध हमेशा कायम रहने चाहिए। यह क्लब सभी आधुनिक सुविधाओं से युक्त बनाया गया है, जहां विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सी.पी. जोशी की सराहना की।

राजस्थान को 'नम्बर वन' बनाना हमारा लक्ष्य

श्री गहलोत ने कहा कि राजस्थान को नम्बर वन राज्य की श्रेणी में लाने का हमारा

लक्ष्य है। इसके लिए मिशन-2030 में सभी की भागीदारी आवश्यक है। वर्तमान में जीडीपी विकास दर में राज्य उत्तरी भारत में नम्बर वन और देश में दूसरे स्थान पर है। विगत 4 वर्षों में राज्य की जीडीपी में 6 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। इस वित्तीय वर्ष के अंत तक राज्य की जीडीपी 15 लाख करोड़ की हो जाएगी। इसे वर्ष 2030 तक 30 लाख करोड़ से अधिक तक ले जाना हमारा लक्ष्य है।

प्रदेश में रही है स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सी.पी. जोशी ने कहा कि राजस्थान में सदैव स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रिया रही है। मोहन लाल सुखाड़िया और भैरों सिंह शेखावत जैसी विभूतियों ने इस परंपरा को कायम रखा। यह क्लब उसी परंपरा को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि जो सदस्य जीतकर वापस सदन में नहीं आ पाते हैं, उनके लिए यह एक आपसी चर्चा और मेल-मिलाप का स्थान

होगा। यहां विधायक एक-दूसरे से वैचारिक चर्चाएं कर पाएंगे एवं उनके आपसी संबंध प्रगाढ़ होंगे। पूर्व सदस्यों के अनुभवों का लाभ नए जीतकर आने वाले सदस्यों को भी मिलेगा। डॉ. जोशी ने कहा कि यह क्लब लोकतंत्र को मजबूत करने का एक प्लेटफॉर्म होगा। क्लब में विषय विशेषज्ञों के साथ ही अनुभवी सदस्यों के साथ मंथन से नए सदस्यों को अपने ज्ञान को बढ़ाने का अवसर मिलेगा। डॉ. जोशी ने कहा कि देशभर में विधानसभा की कार्यवाहियों का औसत समय काफी कम रहता है, यह बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि राजस्थान विधानसभा ने इस संबंध में आदर्श प्रस्तुत किया है। साथ ही, राज्य विधानसभा के विभिन्न नवाचार भी मिसाल बने हैं। उन्होंने कहा कि हम कानून बनाकर देश को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन रूल्स पर अक्सर चर्चा नहीं होती। जनप्रतिनिधियों को रूल्स एवं उनमें संशोधन प्रक्रिया की समझ होनी चाहिए। उन्होंने क्लब के निर्माण के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवाने व अन्य सहयोग के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। साथ ही, आवासन मंडल का भी धन्यवाद व्यक्त किया। नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री श्री शांति धारीवाल ने कहा कि कॉन्स्टीट्यूशन क्लब का निर्माण आवासन मंडल की एक अनूठी योजना है, जो मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष की पहल से साकार रूप ले पाई। आधुनिकतम सुविधाओं के युक्त यह देश का सबसे भव्य और सर्वश्रेष्ठ कॉन्स्टीट्यूशन क्लब है। यहां पर विधानसभा में चुनकर आने वाले नए सदस्यों को पूर्व सदस्यों के अनुभव का लाभ मिल सकेगा। उन्होंने अल्प समय

में क्लब निर्माण के लिए आवासन मंडल को सराहना की। नेता प्रतिपक्ष श्री राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि कॉन्स्टीट्यूशन क्लब का उद्घाटन एक यादगार लम्हा है। लोकतंत्र को मजबूत करने में यह क्लब महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा तथा हमारे विचारों के आदान-प्रदान का मंच बनेगा। उन्होंने क्लब निर्माण के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। साथ ही, विधान सभा अध्यक्ष द्वारा किए गए नवाचारों की सराहना करते हुए कहा कि डॉ. सी.पी. जोशी द्वारा स्थापित किए गए कीर्तिमान देश भर में चर्चा का विषय हैं।

अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त है क्लब

प्रमुख सचिव विधानसभा श्री महावीर प्रसाद शर्मा ने आभार ज्ञापित करते हुए कहा कि व?लब अत्?याधुनिक सुविधाओं से युक्त होगा। आवासन मंडल आयुक्त श्री कुमार पाल गौतम ने बताया कि यह क्लब 4 हजार 950 वर्ग मीटर भूमि पर बनाया गया है। 1 लाख 84 हजार 480 वर्गफीट क्षेत्रफल में निर्मित इस क्लब के निर्माण पर 90 करोड़ रुपये की राशि व्यय होगी। क्लब में रेस्टोरेंट, कॉफी हाउस, स्विमिंग पूल, ऑडिटोरियम, मीटिंग हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, लाइब्रेरी, जिम, सेलून, बैडमिन्टन एवं टेनिस कोर्ट, बिलियर्ड्स व टेबल टेनिस, इंडोर गैम्स सहित अतिथियों के ठहरने के लिए गेस्ट रूम का भी प्रावधान किया जा रहा है। इस अवसर पर राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्य, विधायकगण, मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा, प्रमुख सचिव यूडीएच श्री टी. रविकांत, जयपुर विकास प्राधिकरण आयुक्त डॉ. जोगाराम सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।



महिला आरक्षण बिल जल्द लागू करे सरकार, जातिगत जनगणना, परिसीमन की शर्तें हटाई जाएं; ओबीसी समुदाय को भी शामिल करें : राहुल गांधी

नई दिल्ली, (एजेंसी)। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने महिला आरक्षण बिल लागू किए जाने को लेकर केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। राहुल ने शुक्रवार को कांग्रेस कार्यालय में मीडिया से बातचीत में कहा- केंद्र सरकार महिला आरक्षण बिल अभी से क्यों नहीं लागू करती। इसमें जनगणना और परिसीमन जैसे नियम क्यों जोड़े गए। राहुल ने कहा- महिला आरक्षण अच्छा कदम है, लेकिन इसमें दो शर्तें लगाई गई हैं। इसे लागू करने से पहले जनगणना और परिसीमन कराना होगा। इन्हें करने में बहुत साल लगेंगे। महिला आरक्षण को आज से ही लागू किया जा सकता है। भाजपा को इन दोनों शर्तों को हटकर आरक्षण को तुरंत लागू करना चाहिए। राहुल ने कहा- ये कोई जटिल मामला नहीं है, लेकिन सरकार यह नहीं करना चाहती। ये आज से 10 साल बाद लागू होगा। यह भी नहीं मालूम कि होगा या नहीं होगा। पीएम मोदी रोज ओबीसी के बारे में बात करते हैं लेकिन ओबीसी को महिला आरक्षण में शामिल क्यों नहीं किया? कांग्रेस सत्ता में आने के बाद जातिगत जनगणना कराएगी। तब पता चलेगा कि देश में कितने ओबीसी, दलित और आदिवासी हैं।

उमा भारती बोलीं- ओबीसी कोटा के लिए एक और संशोधन हो : भाजपा नेता उमा भारती ने बताया है कि ओबीसी के सीनियर नेता 23 सितंबर को मीटिंग करेंगे। इसमें वे चर्चा करेंगे कि महिला आरक्षण में ओबीसी कोटा कैसे मिल सकता है। हालांकि, उमा भारती ने मीटिंग की जगह और समय नहीं बताया है। उन्होंने कहा कि जिस ओबीसी आरक्षण की वजह से यह विधेयक 27 साल तक रुका रहा, उसके बिना ही यह पारित हो गया। हमारी पार्टी ने इसे जैसे भी पास किया वह स्वीकार है, लेकिन हम ओबीसी आरक्षण के लिए कोशिश करते रहेंगे। देश की 60 प्रतिशत ओबीसी आबादी के लिए बिल में एक संशोधन और किया जा सकता है।

जब पूर्ण बहुमत की सरकार होती है, तो ऐसे ही मजबूत फैसले लिए जाते हैं : मोदी

नई दिल्ली, (एजेंसी)। महिला आरक्षण बिल (नारी शक्ति वंदन विधेयक) लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद शुक्रवार को भाजपा ने दिल्ली मुख्यालय में जश्न मनाया। महिला कार्यकर्ताओं ने पीएम नरेंद्र मोदी का अभिनंदन और आभार व्यक्त किया। इस मौके पर पीएम ने महिला कार्यकर्ताओं के पैर छूकर आशीर्वाद दिया। मोदी ने 40 मिनट की स्पीच में कहा, मैं आज देश की हर माता-बहन और बेटे को बहुत-बहुत बधाई देता हूँ। कल और परसों 20 और 21 सितंबर को हम सबने एक नया इतिहास बनते देखा है। हम सबका सौभाग्य है कि ये अवसर हमें मिला है। आने वाली हर पीढ़ी तक इस दिवस की और इस निर्णय की चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी के लिए, इस कानून के लिए भाजपा तीन दशक से कोशिश कर रही थी। ये हमारा कमिटमेंट था। इसे



हमने पूरा करके दिखाया है। जब पूर्ण बहुमत की सरकार होती है, तो ऐसे ही मजबूत फैसले लिए जाते हैं। उधर, भाजपा कार्यालय के बाहर सुबह से ही बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता पहुंचने लगी थीं। उन्होंने गुलाल लगाकर और मिठाई बाँटकर बिल के पास होने का जश्न मनाया।

मोदी के स्पीच की बड़ी बातें; कहा- आज हर नारी का आत्मविश्वास आसमान छू रहा : कभी-कभी किसी निर्णय में देश का भाग्य बदलने की क्षमता होती है। हम ऐसे ही

निर्णय के साक्षी हैं। जिस बात को देश को पिछले कई दशकों से इंतजार था। वो सपना अब साकार हुआ है। यह देश के लिए खास समय है। यह भाजपा के हर कार्यकर्ता के लिए भी खास है। आज हर नारी का आत्मविश्वास आसमान छू रहा है। पूरे देश की माताएँ, बहनें बेटियाँ खुशी मना रही हैं। हमें आशीर्वाद दे रही हैं। करोड़ों माताओं बहनों के सपनों को साकार करने का आशीर्वाद हम भाजपा के कार्यकर्ताओं को मिला है। यह हमारे लिए गौरव करने का दिन है। यह कोई

सामान्य कानून नहीं है। यह नए भारत का उद्घोष है। यह बहुत बड़ा और मजबूत कदम है। महिलाओं का जीवन सुधारने के लिए जो गारंटी मोदी ने दी थी, उसका यह प्रत्यक्ष प्रमाण है। मेरे देश की हर माता, बहन और बेटे को मैं फिर से बहुत-बहुत बधाई देता हूँ। इस कानून के जरिए भाजपा महिलाओं की भागीदारी के लिए 3 दशक से प्रयास कर रही थी। यह हमारा कमिटमेंट था। आज हमने इसे पूरा कर दिया है। इसमें कई बाधाएँ थीं, लेकिन जब नीकत पवित्र हो तो परेशानियों को पार करके भी परिणाम लाती है। यह अपने आप में रिकॉर्ड है कि इस कानून को संसद के दोनों सदनों में व्यापक समर्थन मिला। पक्ष-विपक्ष ने भी राजनीति से उठकर इसका समर्थन किया। मैं सबको धन्यवाद देता हूँ।

श्रीनगर में आतंकियों का मद्दगार डीएसपी गिरफ्तार



श्रीनगर, (एजेंसी)। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने आतंकियों की मदद करने के आरोप में गुरुवार को सस्पेंडेड डीएसपीआदिल मुशताक को गिरफ्तार किया है। शेख आदिल पर आतंकवादी गतिविधि में शामिल एक आरोपी मुजाबिल? जहर से 5 लाख रिश्वत लेने और एक अन्य पुलिस अधिकारी को फंसाने का आरोप है। डीएसपी आदिल मुजाबिल जहर से लगातार संपर्क में था। वह उसे टेरर फंडिंग

टेरर फंडिंग केस में दहशतगर्दों को गिरफ्तारी से बचाने का आरोप, 5 लाख रुपए रिश्वत भी ली

केस में लगातार बचाने की कोशिश में लगा हुआ था। पुलिस को आदिल और मुजाबिल के बीच टेलीग्राम ऐप पर चैट और करीब 40 बार फोन पर बातचीत के रिकॉर्ड भी मिले हैं। श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में शेख आदिल के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के विभिन्न प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है। इनमें झूठे सबूत देना और सबूत नष्ट करना भी शामिल है। अन्य पुलिस अफसर को फंसाने में डीएसपी से सहयोग किया : दरअसल, टेरर फंडिंग केस में इसी साल फरवरी महीने में पुलिस ने लश्कर-ए-तैयबा के तीन आतंकियों को गिरफ्तार किया था। उनके पास से 31 लाख रुपए जब्त किए गए थे। तीनों ने पूछताछ के दौरान

मुजाबिल जहर के नाम का खुलासा किया था। जांच के दौरान डीएसपी आदिल और मुजाबिल जहर के बीच संपर्क का खुलासा हुआ। मार्च में डीएसपी आदिल को सस्पेंड कर दिया गया। वहीं पुलिस मुजाबिल की तलाश कर रही थी। इस बीच उसने जुलाई में मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारी के खिलाफ केस दर्ज करा दिया। केस दर्ज कराने के 4 दिन बाद मुजाबिल को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पूछताछ में पता चला कि मुजाबिल ने जिस पुलिस अफसर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी, उसकी शिकायत भी डीएसपी शेख आदिल ने ही ड्राफ्ट की थी। इतना ही नहीं, मुजाबिल को गिरफ्तारी से बचाने के लिए शेख आदिल उसे कानूनी सलाह भी दे रहा था।

महर्षि दधीचि जी की जयंती पर समस्त देश एवं प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं।

वेद प्रकाश दधीचि
अध्यक्ष

विप्र फाउंडेशन, उपखण्ड किशनगढ़
जिला महामंत्री, भाजपा अजमेर शहर